



Civil Judge (Junior Division) — Rajasthan

सिविल न्यायाधीश राजस्थान न्यायिक सेवा का प्रवेश-स्तर का पद है — ज़िला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में बैठने वाला वह न्यायाधीश जिसके सामने दीवानी वाद एवं छोटे आपराधिक प्रकरण आते हैं। काम में साक्ष्य दर्ज करना, पक्षों एवं...



इस करियर की पूरी जानकारी — स्कैन करें

वेतन, परीक्षा, कॉलेज, प्रवेश के रास्ते और आगे के कदम — सब पोर्टल पर।

career.gsssjethantri.in/#/career/raj-civil-judge

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेठन्तरी

Govt. Sr. Sec. School, Jethantri · ब्लॉक समदड़ी · बालोतरा (Block Samdari · Balotra)

www.gsssjethantri.in · career.gsssjethantri.in



सुशील कुमार शर्मा

प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. जेठन्तरी · मास्टर ट्रेनर
Principal, GSSS Jethantri · Master Trainer



श्री चेनाराम चौधरी

प्रधानाचार्य, डाइट बाड़मेर
Principal, DIET Barmer



श्रीमती संघमित्रा

वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट बाड़मेर (सहयोग)
Sr. Lecturer, DIET Barmer (Support)



भरत चौधरी

अभिकल्पना व विकास · व्याख्याता (इतिहास)
Designed & developed · Lecturer (History)

विशेष धन्यवाद · SPECIAL THANKS



सुरेन्द्र सिंह राठौड़

व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. कानाना



सुरेश कुमार सैन

व्याख्याता (भूगोल) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा



वनिता कुमारी

व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा



कमलेश चौधरी

व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) · रा.उ.मा.वि. टापरा

करियर मार्गदर्शन कार्यशाला, डाइट बाड़मेर (14-17 जुलाई 2026) में विकसित व लोकार्पित
Developed & unveiled at the Career Guidance Workshop, DIET Barmer (14-17 July 2026)

यह एक स्वतंत्र परियोजना है, जो सरकार की आधिकारिक करियर-मार्गदर्शन सामग्री पर आधारित है। · An independent project based on the Government's official career-guidance content.

1 यह करियर क्या है

सिविल न्यायाधीश राजस्थान न्यायिक सेवा का प्रवेश-स्तर का पद है — ज़िला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में बैठने वाला वह न्यायाधीश जिसके सामने दीवानी वाद एवं छोटे आपराधिक प्रकरण आते हैं। काम में साक्ष्य दर्ज करना, पक्षों एवं अधिवक्ताओं की सुनवाई, विधि एवं तथ्य पर निर्णय लिखना, तथा प्रक्रिया एवं समय-सीमा का पालन कराना आता है। यह उन थोड़े पदों में है जहाँ प्रवेश ही निर्णायक अधिकार के साथ होता है: पहले दिन से आप किसी के संपत्ति-विवाद, किरायेदारी, अनुबंध अथवा जमानत पर निर्णय दे रहे होते हैं, और उस निर्णय का उस व्यक्ति के जीवन पर सीधा असर पड़ता है। राजस्थान न्यायिक सेवा तीन संवर्गों की है — ज़िला न्यायाधीश, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं सिविल न्यायाधीश — और उनमें से केवल सिविल न्यायाधीश का पद पूर्णतः सीधी भर्ती से भरा जाता है। अर्थात् न्यायिक सेवा में प्रवेश का यही द्वार है, और वहीं से आगे की पूरी सीढ़ी शुरू होती है।

2 एक नज़र में

न्यूनतम योग्यता	विधि स्नातक (प्रोफ़ेशनल) की डिग्री, किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से, जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मान्यता-प्राप्त हो; तथा देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी, राजस्थानी बोलियों एवं राजस्थान की सामाजिक प्रथाओं का गहन ज्ञान (सेवा नियम 2010, नियम 18)
भर्ती संस्था	राजस्थान उच्च न्यायालय / भर्ती प्राधिकारी — यह पद उच्च न्यायालय की देखरेख में आता है, आयोग की सामान्य भर्तियों से भिन्न
आयु-सीमा	21 से 40 वर्ष, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आने वाली 1 जनवरी को — 2018 में यह 23 से 35 से बढ़ाकर 21 से 40 की गई (सेवा नियम 2010, नियम 17) — आरक्षित वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु-सीमा में छूट मिलती है (विवरण नीचे)
आरंभिक वेतन	न्यायिक सेवा का वेतनमान राज्य के सामान्य पे मैट्रिक्स से भिन्न है और राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित रहता है — विज्ञप्ति देखें
माँग	100% सीधी भर्ती — तीन न्यायिक संवर्गों में केवल यही पूर्णतः सीधी भर्ती से भरा जाता है

3 क्या-क्या चाहिए

रुचियाँ

- विधि, न्याय एवं तर्क में गहरी रुचि
- पढ़ने, सुनने एवं निर्णय लिखने का काम
- सार्वजनिक उत्तरदायित्व एवं निष्पक्षता

क्षमताएँ

- निष्पक्षता — यह इस पद की पहली एवं अंतिम कसौटी है
- तथ्य एवं विधि को अलग-अलग देखकर जोड़ने की क्षमता
- दबाव में एवं भावनात्मक प्रकरणों में संयम
- स्पष्ट एवं तर्कसंगत लेखन, क्योंकि निर्णय अपील में पढ़ा जाएगा

ज़रूरी कौशल

- दीवानी प्रक्रिया संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता का व्यावहारिक ज्ञान
- साक्ष्य अधिनियम एवं साक्ष्य का मूल्यांकन
- अनुबंध, संपत्ति, किरायेदारी एवं पारिवारिक विधि
- भारतीय दंड संहिता एवं विशेष अधिनियम
- निर्णय लेखन एवं आदेश की भाषा
- न्यायालय प्रबंधन — प्रकरणों की सूची, समय-सीमा एवं अभिलेख
- हिन्दी एवं राजस्थानी बोलियों की समझ, जो नियम में ही अनिवार्य है

4 कैसे पहुँचें

- 1 कक्षा 12 उत्तीर्ण करें; कला संकाय इस राह के लिए स्वाभाविक है।
- 2 विधि स्नातक (प्रोफेशनल) की डिग्री लें — पंचवर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम अथवा स्नातक के बाद तीन वर्षीय एल.एल.बी.। नियम में शर्त यह है कि डिग्री किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की हो और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मान्यता-प्राप्त हो — इसलिए महाविद्यालय चुनते समय बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया की मान्यता अवश्य जाँचें।
- 3 नियम 18(2) की शर्त को हल्के में न लें: अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी, राजस्थानी बोलियों तथा राजस्थान की सामाजिक प्रथाओं का गहन ज्ञान होना चाहिए। यह औपचारिकता नहीं है — अधीनस्थ न्यायालय में गवाही प्रायः स्थानीय बोली में दी जाती है, और उसे समझे बिना साक्ष्य का मूल्यांकन संभव नहीं। राजस्थान के बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह वास्तविक शर्त है।
- 4 आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ध्यान दें कि यह सीमा 2018 में बढ़ाई गई थी — पहले 23 से 35 वर्ष थी। पुराने स्रोतों अथवा पुरानी विज्ञप्तियों में 23 अथवा 35 दिख सकता है; वे 27-12-2018 से पहले का पाठ हैं।
- 5 नियम 19 के अंतर्गत चरित्र-प्रमाण भी आवश्यक है: अंतिम शिक्षा-संस्थान के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र, तथा आवेदन की तिथि से छह माह के भीतर लिखे गए दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र।

6 भर्ती प्राधिकारी की विज्ञप्ति आने पर आवेदन करें और प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हों।

प्रमुख परीक्षाएँ

- नियम 16 इस पद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात कहता है: सिविल न्यायाधीश संवर्ग के पदों पर भर्ती "केवल सीधी भर्ती से, भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर" की जाएगी। तीनों न्यायिक संवर्गों में यही एकमात्र पद है जो पूर्णतः सीधी भर्ती से भरा जाता है — ज़िला न्यायाधीश एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के पद पदोन्नति एवं अधिवक्ताओं में से भर्ती से भरे जाते हैं।
- आयु में छूट का प्रावधान इस सेवा में अन्य राजस्थान पदों से भिन्न है और उसे ठीक उसी रूप में पढ़ना चाहिए जैसा नियम में है। ऊपरी आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग "तथा महिला अभ्यर्थियों" को दी गई है — बिना किसी वर्ग-शर्त के। राजस्थान के अधिकांश नियमों में महिलाओं को सामान्य वर्ग में 5 वर्ष एवं आरक्षित वर्गों में 10 वर्ष की छूट मिलती है; यह नियम उससे भिन्न ढंग से लिखा गया है।
- इस पृष्ठ पर नीचे दिया गया आयु-छूट का सामान्य विवरण राजस्थान की अनेक सेवाओं पर लागू होता है, पर उसका एक भाग इस पद पर लागू नहीं होता, इसलिए उसे यहीं स्पष्ट किया जा रहा है। विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए ऊपरी आयु-सीमा न होने का प्रावधान राजस्थान की सात सेवा नियमावलियों में पाया गया है, पर राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 में वह प्रावधान 20-08-2020 की अधिसूचना से हटा दिया गया — और हटाए जाने से पहले भी वह "ऊपरी आयु-सीमा 45 वर्ष तक" कहता था, न कि "कोई सीमा नहीं"। अर्थात् इस पद पर आवेदन करते समय उस प्रावधान पर भरोसा न करें।
- परीक्षा कौन कराता है, यह भी नियमों में अलग-अलग है और जानने योग्य है: ज़िला न्यायाधीश के पदों की परीक्षा उच्च न्यायालय कराता है, जबकि सिविल न्यायाधीश की परीक्षा भर्ती प्राधिकारी कराता है। यह पद राज्य के अन्य पदों की तरह लोक सेवा आयोग की सामान्य भर्ती-प्रक्रिया में नहीं आता, इसलिए विज्ञप्ति एवं सूचनाएँ भी अलग स्थान पर प्रकाशित होती हैं।
- और नियम में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है जिसे अवश्य पढ़ लें: "आयु में छूट केवल एक श्रेणी में ही देय होगी।" अर्थात् छूटें जुड़ती नहीं हैं — यदि आप एक से अधिक श्रेणी में आते हैं तो भी छूट एक ही बार मिलेगी।
- यह पद इस परियोजना के अभिलेख में लंबे समय तक "अपुष्ट" के रूप में दर्ज था, केवल इसलिए कि इसे आयोग की विज्ञप्ति-नामों की सूची में खोजा गया था। न्यायिक सेवा की भर्ती आयोग से नहीं होती, इसलिए वह सूची इस प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं सकती थी। सेवा नियम इसे स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं।

- ऊपरी आयु-सीमा में छूट — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; तथा इन्हीं वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसी पद के आगे लिखी बिना छूट वाली आयु किसी आरक्षित वर्ग की महिला के लिए दस वर्ष कम बताती है — यदि आप उस श्रेणी में हैं तो अपनी पात्रता छूट जोड़कर ही तय करें। राजस्थान में सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% पद श्रेणीवार आरक्षित रहते हैं। विधवा एवं परित्यक्ता (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई ऊपरी आयु-सीमा नहीं — नियमों में यही शब्द हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 13(9) में, तथा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियमों के इसी परंतुक में यह प्रावधान दर्ज है, और आर.पी.एस.सी. की विज्ञप्तियाँ भी इसे दोहराती हैं। विधवा को सक्षम अधिकारी से पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र और परित्यक्ता को तलाक का प्रमाण देना होता है। छूट एवं आरक्षण की सटीक शर्तें उसी भर्ती की विज्ञप्ति में दी जाती हैं।

5 कहाँ से पढ़ें

सरकारी संस्थान

- National Law University, Jodhpur — five-year integrated law course — जोधपुर, राजस्थान (<https://nlujodhpur.ac.in/>)
- Government law colleges, Rajasthan — LL.B. — जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर (<https://hte.rajasthan.gov.in/>)
- University of Rajasthan — Faculty of Law — जयपुर, राजस्थान (<https://uniraj.ac.in/>)
- Rajasthan State Judicial Academy — the institution that trains judicial officers after selection — जोधपुर, राजस्थान (<https://home.rajasthan.gov.in>)

ऑनलाइन

- Rajasthan High Court — recruitment notices for the judicial service — यहीं इस पद की विज्ञप्तियाँ प्रकाशित होती हैं, आयोग की वेबसाइट पर नहीं (<https://hcraj.nic.in/>)
- India Code — the bare Acts the examination is built on — भारत सरकार (<https://www.indiacode.nic.in/>)
- eCourts — cause lists, orders and judgments of the subordinate courts — भारत सरकार (<https://ecourts.gov.in/>)

- Bar Council of India — recognition of law colleges, which rule 18 requires — भारत सरकार (<https://www.barcouncilofindia.org/>)
- आर.एस.एस.बी. — पिछले प्रश्न-पत्र, उत्तर कुंजी व पाठ्यक्रम (निःशुल्क) — राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक साइट — तैयारी के लिए सबसे भरोसेमंद निःशुल्क सामग्री (https://rsmssb.rajasthan.gov.in/show_archived?menuName=Xj4lCb9vGxpQnfls%2FxlZ2g%3D%3D)
- विभागीय सेवा नियम (कार्मिक विभाग) — पद की योग्यता व आयु मूल दस्तावेज़ में पढ़ें — कार्मिक विभाग हर संवर्ग के सेवा नियम प्रकाशित करता है। किसी भी कोचिंग सामग्री से पहले यही पढ़ें — योग्यता, आयु और भर्ती की विधि यहीं तय होती है। (<https://dop.rajasthan.gov.in/>)
- स्वयं (SWAYAM) — भारत सरकार के निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स — निःशुल्क (<https://swayam.gov.in/>)
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDLI) — निःशुल्क पुस्तकें व अध्ययन सामग्री (<https://ndli.iitkgp.ac.in/>)
- एन.सी.ई.आर.टी. — निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें — सामान्य ज्ञान, गणित व विज्ञान की नींव (<https://ncert.nic.in/>)

फ़्रीस

एल.एल.बी. राजकीय विधि महाविद्यालयों में बहुत कम शुल्क पर हो जाती है और राजस्थान के हर संभाग में ऐसा महाविद्यालय है; राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर भी राज्य में ही है। महाविद्यालय चुनते समय बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया की मान्यता जाँचना अनिवार्य है, क्योंकि नियम 18 की शर्त ही अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत मान्यता की है — अमान्य संस्थान की डिग्री से पात्रता नहीं बनती और यही वह बिंदु है जहाँ वर्ष एवं शुल्क दोनों व्यर्थ जाते हैं। तैयारी की मुख्य सामग्री निःशुल्क है और यह इस परीक्षा की एक वास्तविक विशेषता है: दीवानी एवं दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, अनुबंध, संपत्ति एवं पारिवारिक विधि तथा राजस्थान के स्थानीय अधिनियम — सबका प्रामाणिक पाठ इंडिया कोड पर उपलब्ध है, और अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं निर्णय ई-कोर्ट्स पर पढ़े जा सकते हैं, जिनसे यह समझ बनती है कि निर्णय वास्तव में कैसे लिखा जाता है। इस परीक्षा में जो पढ़ा जाता है वही आगे रोज़ काम आता है।

छात्रवृत्तियाँ

- Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana (free coaching, apply via SSO) (<https://sso.rajasthan.gov.in/signin>)
- Rajasthan Social Justice and Empowerment Dept scholarships (<https://sje.rajasthan.gov.in/>)
- National Scholarship Portal (NSP) (<https://scholarships.gov.in/>)
- Buddy4Study scholarship search (<https://www.buddy4study.com>)

6 काम कैसा होता है

कहाँ काम

राजस्थान के ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालय — सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, तहसील एवं उप-मंडल स्तर तक। नियुक्ति राज्य के किसी भी ज़िले में हो सकती है और आरंभिक नियुक्ति प्रायः छोटे स्थानों पर होती है; स्थानांतरण नियमित रहते हैं।

कार्य-संस्कृति

यह पद पहले दिन से अकेलेपन का है, और यह बात पहले से जान लेनी चाहिए। न्यायाधीश को न्यायालय के भीतर एवं बाहर एक दूरी बनाए रखनी होती है — अधिवक्ताओं, पक्षकारों एवं स्थानीय समाज से — क्योंकि निष्पक्षता केवल होनी नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। छोटे स्थानों पर, जहाँ आरंभिक नियुक्ति होती है, यह दूरी सामाजिक जीवन को सीमित कर देती है। काम का भार वास्तविक है: प्रकरणों की संख्या अधिक होती है, तारीखें एवं स्थगन दिनचर्या का भाग हैं, और लंबित प्रकरणों का दबाव लगातार बना रहता है। निर्णय लिखना दिन के काम के बाद का काम होता है। इसके बदले में इस पद की संतुष्टि किसी अन्य से भिन्न है: जो आदेश आप लिखते हैं वह किसी के घर, ज़मीन, विवाह अथवा स्वतंत्रता के बारे में होता है, और वह उसी दिन प्रभावी हो जाता है। न्यायिक सेवा में प्रवेश के बाद प्रशिक्षण राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में होता है, और आगे की सीढ़ी — वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, ज़िला न्यायाधीश — इसी संवर्ग से पदोन्नति द्वारा जाती है, इसलिए यह प्रवेश-पद पूरे न्यायिक करियर का आधार है।

कौन नौकरी देता है

- राजस्थान उच्च न्यायालय एवं उसके अधीनस्थ ज़िला न्यायालय
- ज़िला एवं तहसील स्तर के सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय
- राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी — प्रशिक्षण एवं संबद्ध कार्य

माँग (2026)

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियाँ स्थायी रूप से बनी रहती हैं और लंबित प्रकरणों का दबाव इस संवर्ग की आवश्यकता को बनाए रखता है, इसलिए भर्ती अपेक्षाकृत नियमित होती है — यह उन थोड़े पदों में है जिनकी विज्ञप्ति प्रायः लौटती रहती है। एक बात योजना बनाते समय व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण है: यह भर्ती लोक सेवा आयोग से नहीं होती, इसलिए आयोग की वेबसाइट देखते रहने से इसकी सूचना नहीं मिलेगी — विज्ञप्तियाँ राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर आती हैं, और यही वह चूक है जिससे अनेक अभ्यर्थी एक चक्र छोड़ देते हैं। प्रतिस्पर्धा कठिन है और इसे कम करके नहीं आँकना चाहिए, पर उसका स्वरूप समझने योग्य है: पात्रता की शर्तें अपेक्षाकृत सरल हैं — विधि स्नातक एवं आयु — इसलिए आवेदक बहुत होते हैं, और छँटनी परीक्षा की गहराई से होती है, किसी पूर्व-शर्त से नहीं। इसका अर्थ यह है कि तैयारी की गुणवत्ता ही निर्णायक है। साथ ही यह भी जान लें कि 2018 में आयु-सीमा बढ़ाकर 21 से 40 करने से इस पद तक पहुँचने का समय-द्वार काफी चौड़ा हो गया है, और अधिवक्ता के रूप में कुछ वर्ष काम कर चुके व्यक्ति के लिए भी यह खुला रहता है। पदों की संख्या न्यायपालिका की आवश्यकता बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। एक बात स्पष्ट रहे — ऊपर दी गई "माँग" पदों की संख्या बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। चयन खुली प्रतियोगिता से होता है और आवेदन करने वालों की संख्या पदों से कई गुना अधिक रहती है, इसलिए अधिकांश अभ्यर्थी किसी एक भर्ती में चयनित नहीं हो पाते। यह इस करियर के विरुद्ध तर्क नहीं है — बस इसे अपनी एकमात्र योजना न बनाएँ। तैयारी के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखें या कोई कौशल सीखें, ताकि परिणाम चाहे जो हो, वर्ष व्यर्थ न जाए।

7 आगे बढ़ने का रास्ता

- 1 सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) — प्रवेश का पद, 100% सीधी भर्ती; चयन के बाद राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण
- 2 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश — इसी संवर्ग से पदोन्नति द्वारा

- 3 ज़िला न्यायाधीश — पदोन्नति द्वारा, तथा अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भी (उसके लिए आयु 35 से 45 वर्ष एवं परीक्षा उच्च न्यायालय कराता है)
- 4 उससे आगे उच्च न्यायालय की न्यायपालिका में नियुक्ति के अवसर, जो संवैधानिक प्रक्रिया से होते हैं

कमाई

शुरुआत	न्यायिक सेवा के वेतनमान के अनुसार — विज्ञप्ति देखें
मध्य स्तर	₹1,10,000 – ₹1,50,000 (भत्तों सहित, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश स्तर पर)
वरिष्ठ स्तर	₹1,60,000 से अधिक (भत्तों सहित, ज़िला न्यायाधीश स्तर पर)

न्यायिक सेवा का वेतन राज्य के सामान्य पे मैट्रिक्स से भिन्न है और राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित रहता है, इसलिए इसकी तुलना अन्य राज्य-सेवा पदों से सीधे नहीं की जा सकती — यह उनसे ऊपर रहता है। 2010 के सेवा नियमों में वेतनमान का आँकड़ा इस पृष्ठ के लिए नहीं लिया गया, इसलिए आरंभिक वेतन यहाँ नहीं लिखा गया; वह विज्ञप्ति में मिलेगा। ऊपर दिए मध्य एवं वरिष्ठ स्तर के आँकड़े अनुमानित हैं और किसी आधिकारिक दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं; उन्हें दिशा समझें, वचन नहीं। वेतन के अतिरिक्त इस पद पर सरकारी आवास, वाहन एवं अन्य सुविधाएँ न्यायिक सेवा के नियमों के अनुसार मिलती हैं। शुरुआती वेतन का आँकड़ा मूल वेतन है, ताकि इसे दूसरे करियर के साथ सीधे तुलना किया जा सके। इस पर महँगाई भत्ता (1 जनवरी 2026 से मूल वेतन का 60%) एवं मकान किराया भत्ता अलग से जुड़ते हैं, इसलिए हाथ में आने वाली राशि इससे काफ़ी अधिक होती है। मध्य-स्तर व वरिष्ठ स्तर के आँकड़े भत्तों सहित अनुमानित मासिक आय हैं, मूल वेतन नहीं। ध्यान दें — राजस्थान में सीधी भर्ती से लगे कर्मचारी पहले 2 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रहते हैं और इस अवधि में वेतनमान नहीं, बल्कि एक नियत पारिश्रमिक मिलता है; इन दो वर्षों में महँगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता देय नहीं होते (राजस्थान सेवा नियम, नियम 7(30क))। पूरा वेतनमान परिवीक्षा पूरी होने के बाद लागू होता है। इस पद का पे मैट्रिक्स स्तर इस पृष्ठ पर आधिकारिक दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं किया जा सका — न सेवा नियमों में, न सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूची में। इसलिए यहाँ कोई स्तर नहीं लिखा गया है। सही आँकड़ा उस भर्ती की आधिकारिक विज्ञप्ति में दिया जाता है; आवेदन से पहले उसे अवश्य देखें। ऊपर दिए गए आँकड़े राजस्थान के सातवें वेतन मैट्रिक्स पर आधारित हैं, जो 17 अगस्त 2026 तक लागू है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की शर्तें 28 अक्टूबर 2025 को स्वीकृत हुई थीं और आयोग को गठन से 18 माह के भीतर सिफ़ारिशें देनी हैं। राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ, और कुछ देर से, लागू करती हैं — इसलिए राजस्थान का वेतनमान भी आगे संशोधित होगा, यद्यपि कब और कितना, यह अभी तय नहीं है।

8 अच्छी बातें • चुनौतियाँ

अच्छी बातें

- न्यायिक सेवा में प्रवेश का एकमात्र पूर्णतः सीधी भर्ती वाला द्वार
- पहले दिन से वास्तविक निर्णायक अधिकार एवं सार्वजनिक उत्तरदायित्व
- पात्रता की शर्तें सरल — विधि स्नातक एवं आयु: कोई पूर्व-अनुभव आवश्यक नहीं
- तैयारी की सामग्री लगभग पूरी निःशुल्क, और वही आगे रोज़ काम आती है
- 2018 में आयु-सीमा 21 से 40 होने से समय-द्वार चौड़ा
- वेतनमान राज्य-सेवा के अन्य पदों से ऊपर

चुनौतियाँ

- यह अकेलेपन का पद है — निष्पक्षता के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखनी पड़ती है
- लंबित प्रकरणों का दबाव एवं निर्णय-लेखन का अतिरिक्त भार
- नियुक्ति एवं स्थानांतरण राज्य में कहीं भी, आरंभ प्रायः छोटे स्थानों से
- विज्ञप्ति उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर आती है, आयोग की नहीं — इसी चूक से अभ्यर्थी चक्र छोड़ देते हैं
- विधवा/परित्यक्ता की आयु-छूट का प्रावधान इस सेवा में 2020 में हटा दिया गया, अन्य सेवाओं के विपरीत

9 अगर यह रास्ता न बने तो

एक परीक्षा या एक प्रयास से रास्ता बंद नहीं होता। इन्हीं विषयों से ये रास्ते भी खुलते हैं — इनमें प्रवेश आमतौर पर आसान होता है और आगे चलकर इसी क्षेत्र में लौटा जा सकता है।

- सहायक अभियोजन अधिकारी (राजस्थान)
- कनिष्ठ विधि अधिकारी (राजस्थान)
- न्यायाधीश

10 स्रोत व आगे पढ़ें

1. कार्मिक विभाग, राजस्थान — राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 — <https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/modulCategory/202303210354592432088judical2010merged.pdf>
2. राजस्थान उच्च न्यायालय — भर्ती सूचनाएँ — <https://hcraj.nic.in/>
3. गृह विभाग, राजस्थान — राज्य न्यायिक अकादमी की अपनी साइट वर्तमान में उपलब्ध नहीं — <https://home.rajasthan.gov.in>

4. इंडिया कोड — केंद्रीय एवं राज्य अधिनियम — <https://www.indiacode.nic.in/>
5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आधिकारिक) — <https://rssb.rajasthan.gov.in/>
6. कार्मिक विभाग, राजस्थान — सेवा नियम — <https://dop.rajasthan.gov.in/>
7. आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग — मंत्रिमंडल की स्वीकृति (पी.आई.बी., 28 अक्टूबर 2025) — <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183289>

**और 770+ करियर — पूरा पोर्टल**

रुचि व योग्यता परीक्षण, सरकारी नौकरियाँ, कौशल पाठ्यक्रम, बायोडाटा बनाने की सुविधा — सब मुफ्त, बिना लॉगिन, इंटरनेट के बिना भी।

career.gssjsjethantri.in